

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया :-

न मोदी-न माया, यूपी को कांग्रेस-सपा गठबंधन भाया

हार सामने देख मोदी घबराए- भददी भाषा, झूठे बोल भी काम न आए

किसान से विश्वासघात, रोजी-रोटी पर कुठाराघात, यही है मोदी के 'मन की बात'

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-सपा गठबंधन विजय की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर भाजपा की सुनिश्चित हार देख प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी बौखलाए, झुंझलाए व घबराए हैं।

स्वघोषित दत्तक पुत्र नरेन्द्र मोदी - न गंगा का, न गाँव का

मोदी जी के नेतृत्व में 'बीजेपी' की नई संज्ञा है - 'बहुत झूठी पाठशाला'। प्रधानमंत्री जी अपनी अकर्मण्यता का दाग अंततः झूठ, नफरत व बंटवारे के प्रचार संस्थान के प्रधानाचार्य बनकर धोना चाहते हैं। यूपी की मिट्टी ने कभी झूठों को पैदा नहीं किया। मोदीजी, आप किस मिट्टी के बने हैं? माँ गंगा की सौगन्ध खाते हैं, उसे चोट पहुँचाते हैं। किसानों की कसमें खाते हैं, उसे धोखा दे जाते हैं। सत्ता के ढाई साल और यूपी के 73 सांसदों के काम का हिसाब पूछें तो नफरत और बंटवारे का मुखौटा लगाते हैं। इतना ही नहीं मौत को भी धर्म के आवार पर बाँटकर बस वोट पाना चाहते हैं।

मोदी जी के जुमलों की यही सच्चाई है। विपक्ष और किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा, 'फसलों के दाम दे दो'। पर वो कहते हैं, 'फसल बर्बाद हो जाने दो, बीमा दूंगा'। देश के नागरिक कहते हैं, 'अच्छी जिंदगी दीजिए'। वो कहते हैं, 'मर जाने दो, 1 लाख का बीमा दूंगा।' लोग कहते हैं, 'जिंदगी जीने के लिए रोटी-रोजगार दीजिये'। मोदी जी कहते हैं, 'शमशान और कब्रिस्तान दूंगा'। कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी मणिपुर के पाईनेपल व संतरों के जूस के निर्यात को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, तो मोदी जी झूठे जुमलों से उसे भी 'नारियल का जूस' बना देते हैं। परंतु यूपी के लोग 'झूठ के जूस' और 'सच के रस' में अंतर समझते हैं।

किसान से धोखा - लागत + 50% मुनाफा खारिज व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी नामंजूर

आज समूचा उत्तर प्रदेश और उसके 2 करोड़ 32 लाख किसान परिवार भाजपाई झूठ का हिसाब करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश, देश का सबसे ज्यादा गेहूँ उत्पादन करता है, जो देश के कुल उत्पादन का 32% है, यानि लगभग 283 लाख टन। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है, यानि कुल उत्पादन का 12.5% या 125 लाख टन।

साल, 2014 में मोदीजी ने कसम उठाई कि वो फसल की कीमत पर 50% मुनाफा देंगे व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। प्रधानमंत्री बनकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथपत्र दिया कि किसान की लागत पर 50% मुनाफा देना संभव नहीं। इस शपथपत्र की प्रतिलिपि संलग्नक A1 है। यही नहीं, आरटीआई के जवाब में 50% मुनाफा व स्वामीनाथन आयोग, दोनों को ही खारिज कर डाला, जिसकी कॉपी संलग्नक A2 है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद – मोदीजी का झूठ

इससे भी शर्मनाक व अन्यायपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश 'नॉन डीसेन्ट्रलाइज्ड प्रिक्वोरमेंट स्टेट' है यानी कि किसान के अनाज की खरीद की सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है प्रतिलिपि संलग्नक A3 है। पर केंद्र की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के किसान का अनाज 'समर्थन मूल्य' पर नहीं खरीदती।

शर्मनाक बात यह है कि जहाँ 2016-17 में देश में 229.30 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार ने खरीदा वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 7.97 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, अर्थात् लगभग 3.47%। इसी प्रकार पूरे देश में केंद्रीय सरकार ने 2016-17 में 223.12 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा, परंतु हैरत की बात है कि उत्तर प्रदेश के किसान से मात्र 6.37 लाख टन धान, अर्थात् मात्र 2.85% खरीदा गया। विडम्बना यह है कि लागत + 50% मुनाफा देना तो दूर, उत्तर प्रदेश के किसानों को घोखा देकर उनसे समर्थन मूल्य पर अनाज भी मोदी सरकार नहीं खरीदती।

Procurement of Wheat in Uttar Pradesh

Marketing Seasons	Wheat Production U.P. (Lakh Tonne)	Wheat Procurement - U.P. (Lakh Tonne)	All India Wheat Procurement (Lakh Tonne)	U.P. Procurement as % of Total Procurement
2014-15	224.17	6.28	280.23	2.24%
2015-16	283.65	22.67	280.88	8.07%
2016-17	--	7.97	229.30	3.49%

Procurement of Rice in Uttar Pradesh

Marketing Seasons	Paddy Production U.P. (Lakh Tonne)	Paddy Procurement - U.P. (Lakh Tonne)	All India Paddy Procurement (Lakh Tonne)	U.P. Procurement as % of Total Procurement
2014-15	121.68	16.98	320.40	5.29%
2015-16	125.09	29.10	341.42	8.5%
2016-17	--	6.37	223.12	2.85%

दिनांक 02.01.2017 की स्थिति के अनुसार

विदेशी गेहूँ का आयात— किसान से विश्वासघात

मोदी सरकार ने सितम्बर, 2016 में गेहूँ की इम्पोर्ट ड्यूटी 25% से घटाकर 10% कर दी थी और अब दिसम्बर, 2016 में इसे 0% कर देश के किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम किया है।

यही नहीं, गेहूँ का दूसरे देशों में निर्यात कांग्रेस सरकार के समय 2013-14 में 55 लाख टन था। मोदी जी के शासन में साल, 2015-16 में यह निर्यात घटकर 6 लाख टन रह गया।

गेहूँ आयात

April 2015 - March 2016		April 2016 - December 2016	
Quantity (Lakh Tonne)	Value (Crore)	Quantity (Lakh Tonne)	Value (Crore)
5.17	872.08	18.94	2744.96

गेहूँ निर्यात

Product	2013-14		2014-15		2015-16	
	Qty. (Lakh Tonne)	Rs. Crore	Qty. (Lakh Tonne)	Rs. Crore	Qty. (Lakh Tonne)	Rs. Crore
Wheat	55.62	9261.60	29.24	4991	6.18	978

गरीबों पर कराच प्रहार— ऐसी रही मोदी सरकार

कल ही मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के भाव में 86 रु. की बढ़ोतरी की। गैस सिलेंडर के भाव मोदी जी 6 बार बढ़ा चुके, यानि सितंबर, 2016 में 466 रु. से बढ़ाकर अब 733 रु. प्रति सिलेंडर। दो साल में इस प्रकार 271 रु. प्रति गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी, जो 58% से अधिक है। यही नहीं डिजिटल इंडिया और कैशलेस का हवाला देने वाली मोदी सरकार ने 2015 में ATM की 5 ट्रांजैक्शंस से ज्यादा पर 20 रु. शुल्क लगाया। और कल ही चोर दरवाजे से बैंकों/ ATM ट्रांजैक्शन पर 4 से ज्यादा निकासी पर 150 रु. का शुल्क लगा दिया।

एक और प्रहार यूपी सहित देश के सभी राज्यों में राशन की दुकान से मिलने वाली चीनी यानि रियायती दर को खत्म करने का है। भारत सरकार राशन की चीनी पर 18.50 रु. प्रतिकिलो के हिसाब से राज्य सरकारों को देती है और राज्य सरकारें राशन की दुकान के माध्यम से यही चीनी 13.50 रु. किलो से लेकर 20 रु. किलो की रियायती दर पर लोगों को उपलब्ध करवाती है। इस पर केंद्र सरकार को सालाना पूरे देश में 4500 करोड़ रु. का खर्च आता है। 1 अप्रैल, 2017 से मोदी सरकार ने इस सब्सिडी को खत्म कर देश के करोड़ों लोगों के मुंह में कड़वाहट घोल दी।

नोटबंदी या विकासबंदी

नोटबंदी के दुष्परिणामों से उत्तर प्रदेश का हर शहर और उद्योग मंदी के भयावह दौर से गुजर रहा है। अलीगढ़ के 'ताला उद्योग' पर ताला लग गया है, आगरा का 'जूता एवं पैठा उद्योग', कानपुर का 'चमड़ा उद्योग', मिर्जापुर भदोही का 'कालीन उद्योग', बनारस का 'साड़ी व्यापार', खुर्जा के 'चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग', मेरठ का 'रेवड़ी उद्योग', लखनऊ का 'चिकनकारी उद्योग', बरेली का 'भांझा व बांस फर्नीचर उद्योग', मुरादाबाद का 'पीतल उद्योग' जैसे सभी स्थानीय रोजगार ठप्प हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। पूरे देश में करीब 2.25 करोड़ मध्यम एवं लघु उद्योग हैं, जिनमें से बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है। नोटबंदी के कारण ये सारे उद्योग मंदी की मार झेल रहे हैं और बंद होने की कगार पर हैं। नोटबंदी की वजह से उत्तर प्रदेश का 'खांडसारी एवं कोल्हू उद्योग' पूर्णतया चौपट हो गया है। बेरोजगारी दूर करने के अपने वायदे पर श्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में कुल 1,40,000 युवाओं को ही रोजगार दिया (सन 2016, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार)।

भाजपा और अपराध का 'घोली दामन' का साथ

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की अलौकिक और पवित्र भूमि को 'अपराधियों का गढ़' कहकर लगातार बदनाम कर रहे हैं।

देश के गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे कि क्या जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो यूपी में प्रतिवर्ष 7,610 'हत्याएँ' और 7,964 'हत्या के प्रयास' नहीं हुआ करते थे? आज अखिलेश सरकार में हत्या के प्रकरण आधे रह गये हैं अर्थात् 4,732 और हत्या के प्रयास 4,897, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी साल 2001 की तुलना में काफी बढ़ी है। हमारा मानना है कि कांग्रेस सपा गठबंधन और अधिक तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

दुर्भाग्य से मोदी जी यूपी को लगातार 'बलात्कार व महिला उत्पीड़न' के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। यूपी जानना चाहता है कि क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4,391 बलात्कार देश में सबसे ज्यादा नहीं है ? दूसरे नंबर पर भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र है जहाँ प्रतिवर्ष 4,114 अबलाओं से होते बलात्कार का शर्मनाक आंकड़ा है। तीसरे नंबर पर भाजपा शासित राजस्थान है, जहाँ बलात्कारों की संख्या 3,644 है, जबकि यूपी की आबादी इन राज्यों से दुगुनी और तीन गुनी है। 'महिलाओं से छेड़छाड़ व इज्जत पर हमले' वाले अपराधों में भी भाजपा शासित महाराष्ट्र पूरे देश में 11,713 प्रकरणों के साथ पहले नम्बर पर है। दूसरे नम्बर पर 8,049 प्रकरण के साथ भाजपा शासित मध्यप्रदेश है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के तहत होने वाले 'कुल यौन अपराधों' में भी भाजपा शासित महाराष्ट्र 16,989 प्रकरणों के साथ देश में पहले स्थान पर है और भाजपा शासित मध्यप्रदेश 12,887 प्रकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है। मोदी जी अगर 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' की रिपोर्ट (जो कि गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जारी करते हैं) पढ़ लेते, तो शायद इतना झूठ न बोलना पड़ता।